महाराष्ट्र सरकार से राहत की मांग करेंगी चीनी मिलें

[जयश्री भोसले | पुणे]

महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी जैसी चीनी कारोबार के दिग्गजों से भरी पार्टियों के सहयोग वाली नई सरकार से चीनी मिलें राज्य में बाढ़ के कारण चीनी उत्पादन में हो सकने वाली कमी को देखते हुए राजकोषीय राहत मांगने की तैयारी कर रही हैं। गन्ने की खेती वाले इलाके करीब 15-20 दिनों तक पानी में डूबे थे। इससे गन्ने के विकास और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा है।

मिल मालिकों का दावा है कि प्रति टन गन्ने से बनने वाली चीनी की मात्रा में काफी गिरावट आएगी। इसे मिलर्स की भाषा में शुगर रिकवरी कहा जाता है। कोल्हापुर के अनुभवी शुगर एक्सपर्ट आर जी मेधे ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सरकार शुगर रिकवरी में गिरावट की भरपाई करे।' मिल मालिकों का कहना है कि मिलें चालू वर्ष में चीनी की रिकवरी पर ध्यान दिए बिना पिछले वर्ष की रिकवरी के आधार पर किसानों को गन्ने का भुगतान करती हैं। मेधे ने कहा, 'पिछले साल रिकवरी ज्यादा थी, इसलिए हम इस साल कम रिकवरी के बावजूद ज्यादा कीमत चुकाएंगे।' महाराष्ट्र कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खटाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मिल मालिकों का संगठन ऐसी मांग करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'रिकवरी के नुकसान की भरपाई जरूरी है क्योंकि मिलों को बड़े अनसोल्ड स्टॉक की वजह से सीजनल लोन नहीं मिल रहा है।' हालांकि, महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री को नई सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया उम्मीद है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के चीनी कारोबार के दिग्गज शामिल हैं।

बाढ़ से गन्ने की फसल पर असर पड़ा है जिससे इस सीजन में शुगर रिकवरी कम होने का डर है

Economic times

2/12/19.